राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

देश की उपासना

जौनपुर से प्रकाशित

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

प्रधानाचार्य परिषद के ग्रीष्मकालीन चिन्तन शिविर के लिये तैयारियां तेज

बस्ती, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के ग्रीष्मकालीन चिन्तन शिविर एवं प्रादेशिक सम्मेलन में प्रधानाचार्यों की समस्याओं के समाधान की भावी रणनीति तय होगी । इसके साथ ही विद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के उपायों पर भी व्यापक विचार विमर्श होगा ।यह दावा 13 व 14 जून को राजकीय इंटर कालेज बस्ती के बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित होने वाले सम्मेलन की सफलता के लिए स्काउट भवन में तैयारी बैठक में मौजूद सभी प्रधानाचार्यों ने एक स्वर में किया। परिषद के जिला संरक्षक मार्कण्डेय सिंह, डा संजय सिंह, डा०घनश्याम श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष योगेश शुक्ल व मंत्री डा हरेंद्र प्रताप सिंह ने सम्मेलन के आयोजन हुआ।

वर्ष – 03 | अंक – 283 | जौनपुर | सोमवार, 02 जून 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त समाचार

सीमापुरी में फ्लैट में भाई–बहन की जोड़ी लटकी हुई मिली

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पुलिस ने बताया कि रविवार को दिल्ली के सीमापुरी में एक 32 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 30 वर्षीय बहन अपने किराए के फ्लैट में लटके हुए पाए गए। घटना तब सामने आई जब पड़ोसियों ने उनके ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट से दुर्गंध आने की सूचना दी। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत में फतेहपुर चक, किशनपुर, रमाला निवासी देवेंद्र कुमार के बेटे वीरेश कुमार तोमर और उनकी बहन चिंकी तोमर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि भाई–बहन 2021 से फ्लैट में रह रहे थे। वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है मांग क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (थ्ै) के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे की जांच के लिए इलाके की वीडियोग्राफी की गई। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में आत्महत्या का संकेत दिया गया है, अधिकारी अन्य विवरणों की पुष्टि कर रहे हैं। अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

सोने के व्यापार घोटाले में 41 लाख रुपये की ठगी, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दक्षिण–पश्चिम दिल्ली में कथित चीनी लिंक वाले दो जालसाजों को डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग के जरिए उच्च रिटर्न के बहाने एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी से 41.45 लाख रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इंद्र कुमार साहनी (36) और रहीम खान (24) के रूप में पहचाने गए दोनों ने एक बहुस्तरीय साइबर धोखाधड़ी अभियान चलाया, जिसमें खच्चर बैंक खाते बनाए और विदेशी संचालकों को फंड ट्रांसफर की सुविधा दी। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, कथित मुख्य संचालक रहीम खान एक मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए चीनी नागरिकों के संपर्क में था। डीसीपी ने कहा, वह पूरे भारत के खाताधारकों के साथ समन्वय करता था, उन्हें अहमदाबाद के होटल के कमरों में लाता था, जहां वह धोखाधड़ी का नेटवर्क संचालित करता था। चौधरी ने कहा कि खान ने बैंक खातों में पंजीकृत सिम कार्ड से जुड़े उपकरणों पर विशिष्ट ऐप इंस्टॉल किए। , जिससे विदेशी–आधारित स्कैमर्स को अवैध फंड ट्रांसफर के लिए खातों तक दूरस्थ पहुंच मिल गई। कथित तौर पर यूएसडीटी, एक क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया और भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हुए विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया। डीसीपी ने कहा कि मामला तब प्रकाश में आया जब वसंत कुंज में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्नल शिकायतकर्ता को एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करने का लालच दिया गया। उन्होंने कहा, ष्सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क किया गया, जहां उन्हें डॉलर में सोने के व्यापार के जरिए महत्वपूर्ण रिटर्न का वादा किया गया था। शुरुआती जमा के बाद, फर्जी साइट पर उनके खाते में तेजी से लाभ संचय दिखाया गया, जिससे आगे और निवेश हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने कुल 41.45 लाख रुपये का निवेश किया, यह मानते हुए कि उसका रिटर्न बढ़कर 1 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन जब उसने अपनी कमाई निकालने का प्रयास किया।

आम जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख : सीएम योगी

लखनऊ, (एजेंसी)। प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की ही तरह यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने पर मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया तो आगामी पंचायत चुनाव में ही इस नई चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जायेगा। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके चर्चा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा कि वह अधिकारियों को निर्देशित करें कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव तैयार कर इसे जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाए जिससे समय रहते इसकी तैयारी की जा सके। राजभर का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनके इस प्रस्ताव से सहमति जताई है और जल्द ही प्रस्ताव केंद्र को भेजने का आश्वासन भी दिया है।उन्होंने कहा कि वह पिछले चुनाव में ही यह चाहते थे। अधिकारियों से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराने के लिए कहेंगे। इस मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश राजभर के पुत्र सुभासपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर भी साथ थे।

अपराध न्याय प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक बनाया जाएगा : अमित शाह

कोलकाता, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार का मुख्य लक्ष्य पूर्णतः साक्ष्य आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करना है और इसे प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, हमारा लक्ष्य आपराधिक न्याय प्रणाली को साक्ष्य आधारित बनाना है, न कि बहस आधारित, ताकि व्यवस्था में संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक अपराधी को संदेह का लाभ न मिले और साथ ही पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित हो सके,ष उन्होंने कहा। सवाल उठाए गृह मंत्री शाह ने रविवार को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में राजारहाट में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएसएफएल) के नए भवन का उद्घाटन

किया। इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक प्रतिष्ठित और पूर्णतः साक्ष्य आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए, जांचकर्ताओं को हमेशा अपराधियों से दो कदम आगे रहना चाहिए। शाह ने कहा, ष्इसमें तकनीक की सबसे अहम भूमिका होगी, जहां जांचकर्ता अपराधियों से दो कदम आगे रहेंगे। डीएनए सीक्वेंसिंग की वजह से हम 20 साल पुराने आपराधिक मामलों को सुलझाने में सफल हुए हैं। फोरेंसिक ऑडिट की वजह से कई वित्तीय अपराधों को सुलझाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार देश में फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 2,800 करोड़ रुपये की परियोजना लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाइल्डर्स आए समर्थन में साथ ही, 200 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा : नड्डा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान

में चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना केन्द्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल है। नड्डा यहां मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं, जिनसे 'निरामय राजस्थान' की संकल्पना साकार होने लगी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार नड्डा ने राजस्थान में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की सराहना की। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि स्वस्थ राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

दिल्ली की बेहतरी के लिए 100 दिन काम किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ईमानदार शासन, जन कल्याण और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है, जबकि उन्होंने पिछली सरकार पर नागरिक उपेक्षा का आरोप लगाया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गुप्ता ने अवास्तविक वादे करने के बजाय ठोस नीतियां बनाने पर अपने प्रशासन के जोर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ष्मेरी सरकार ने नीतियां बनाने और दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करने में 100 दिन बिताए। हम झूठे वादे नहीं कर सकते। हम यमुना की सफाई और कूड़े के ढेरों को हटाने जैसे मुद्दों को हल करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं।ष गुप्ता ने निजी स्कूलों में फीस को विनियमित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश लाने की योजना की घोषणा की। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा उन्होंने कहा, ष्शिक्षा सुलभ और निष्पक्ष होनी चाहिए।ष सीएम ने वय वंदना योजना की भी प्रशंसा की, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। उन्होंने कहा, ष्लगभग 1. 5 लाख पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं।ष पिछली आप सरकार पर

निशाना साधते हुए गुप्ता ने उस पर जनता के भरोसे को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ष्हजारों लोग बदलाव की उम्मीद में आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन जिन लोगों ने दावा किया कि उन्हें सत्ता की कोई भूख नहीं है, वे सत्ता की भूख में खो गए।ष पिछली सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए उन्होंने सवाल किया, ष्जब यमुना की सफाई पर कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया गया, तो राष्ट्रीय राजधानी सबसे प्रदूषित कैसे हो सकती है?

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति हो रही खरब है : मायावती

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने रविवार को विभिन्न राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मायावती ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में लिखा, ष्देश के विभिन्न राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश में सामंती और आपराधिक तत्वों के वर्चस्व के कारण जातिवादी और सांप्रदायिक घृणा, हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न तथा लोगों का विस्थापन आदि की घटनाएं साबित करती हैं हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा कि यहां कानून का शासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह भी पढ़ें – कांग्रेस प्रमुख ने पाकिस्तान की बात दोहराईरू गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे की टिप्पणी पर निशाना साधा उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि उत्तर

प्रदेश पुलिस के नए प्रमुख के सामने अपराध को नियंत्रित करने और राज्य में कानून का शासन स्थापित करने में बड़ी चुनौती है। मायावती ने कहा, ष्ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए मुखिया के सामने अपराध पर नियंत्रण और राज्य में कानून का राज स्थापित करने तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों को समुचित राहत प्रदान करने की बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल के लोगों को भी यूपी में कानून का राज स्थापित करने में हर तरह के सहयोग और सक्रियता की जरूरत है। मांग बसपा प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश को भारत के बहुआयामी विकास में अहम भूमिका निभानी चाहिए और अपनी विशाल आबादी की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्य की प्रतिष्ठा नकारात्मक चर्चाओं, खासकर अपराध नियंत्रण और खराब कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित चर्चाओं से प्रभावित हो रही है।उन्होंने अफसोस जताया कि देश के विकास इंजन के तौर पर देखे जाने के बजाय, यूपी को अक्सर इन चुनौतियों से जोड़ा जाता है, जो जनता की धारणा और राष्ट्रीय हित दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। । न्यूनतम बैलेंस इससे पहले मई में मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की शबिगड़ती स्थितिश की भी आलोचना की थी और स्थिति को बहुत दयनीय बताया था।उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह जारी रहा तो इससे हाशिए पर पड़े समुदायों के शैक्षिक भविष्य को खतरा होगा।इस प्रवृत्ति को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए, बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार को बुनियादी शिक्षा के महत्व को पहचानना चाहिए और तत्काल सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए की ही सरकार बनेगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एंट्री लेने के लिए तैयार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। जिसमें चिराग पासवान भी आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। चिराग के चुनाव लड़ने पर राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) नेता मलूक नागर ने कहा कि यह अच्छी बात है वह बड़े नेता हैं। वह चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी को ही मजबूती मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा विधायक उनकी पार्टी से चुनकर आएंगे तो यकीनन उनकी पार्टी और एनडीए के लिए यह फायदेमंद साबित होगा। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव की ओर से 'एक्स' पर अपने माता–पिता को लेकर किए गए एक

पोस्ट को लेकर आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा यह उनका निजी मामला है। लेकिन, इस देश में सभी को अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी है। उन्होंने कहा कि कभी दूरियां पैदा होती हैं, कभी विचारधारा में मतभेद होता है, तो कभी राजनीतिक परिवारों में सत्ता की महत्वाकांक्षा होती है। कई बार चिंता होती है कि ये मुद्दे राजनीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर तब जब 3–4 महीने में चुनाव आने वाले हैं। परिवार इन सभी बातों पर विचार करता है। अगर कोई फैसला सख्ती से लिया गया और अब उन्हें लगता है कि शायद यह एक गलती थी। हालांकि, परिवार को देखकर चलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के सवालों पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है। 22 अप्रैल के बाद जितने भी सवाल कांग्रेस की ओर से पूछे गए वह पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बनी है। सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद भी सवाल पूछते हैं।

गरीबों के लिए काम करती है आंध्र प्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री नायडू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री ने जल्द ही तीन किस्तों में अन्नदाता सुखीभव (किसानों को प्रति वर्ष 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता) लागू करने का भी वादा किया। इसी तरह, उन्होंने 15 अगस्त से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा लागू करने का भी आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कहा कि तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार

गरीबों के लिए काम करती है और उनके लिए सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। जिले के चेयेरू में एक ग्राम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 64 लाख से अधिक लोगों को हर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों की तरह ही पेंशन मिलती है। नायडू ने कहा, यह सरकार गरीबों के लिए काम करती है। हम गरीबों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए सभी कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरित करने के मामले में राजग सरकार इतिहास में एक अनोखी सरकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक कल्याणकारी पेंशन पर 34,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे अमीर राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश संख्या और धन की दृष्टि से अधिक कल्याणकारी पेंशन देता है। दीपम–2 योजना का उल्लेख करते हुए (जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को तीनरसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाते हैं) मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस योजना के लाभ को आसान बनाने के लिए चार महीने में एक बार लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा जमा करेंगे। मुख्यमंत्री ने जल्द ही तीन किस्तों में अन्नदाता सुखीभव (किसानों को प्रति वर्ष 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता) लागू करने का भी वादा किया।

भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 3000 के पार, केरल और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित

केरल, (एजेंसी)। भारत में सक्रिय कोविड–19 मामलों की संख्या 3,000 को पार कर गई है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली नवीनतम लहर में सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, देश में वर्तमान में 3,395 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से केरल में सबसे अधिक 1,336 मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 467 और अन्य राज्यों में भी मामले बढ़ रहे हैं। केरल भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां शुक्रवार को 189 नए कोविड मामले दर्ज किए गए और वर्तमान में 1,336 सक्रिय संक्रमण हैं। इसके बाद महाराष्ट्र (467), दिल्ली (375), गुजरात (265), कर्नाटक (234), पश्चिम बंगाल (205), तमिलनाडु (185) और उत्तर प्रदेश (117) जैसे

राज्य हैं, जहां कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। अन्य प्रभावित राज्यों में राजस्थान (60), पुडुचेरी (41), हरियाणा (26), आंध्र प्रदेश (17) और मध्य प्रदेश (16) शामिल हैं। भारत में इस साल अब तक 26 कोविड से संबंधित मौतें दर्ज की गई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (प्ब्डत्) ने कहा है कि भारत में कोविड के मामलों में उछाल का कारण ओमीक्रॉन के उप–वेरिएंट हैं, जो 2022 में भारत में कोविड की बड़ी लहर के पीछे एक स्ट्रेन था। प्रमुख डॉ. राजीव बहल ने कहा कि ये वेरिएंट स्थ.7, ग्थ्ठ, श्रछ.1 और छठ.1.8.1 हैं, जिनमें से पहले तीन अधिक प्रचलित हैं। डॉ. बहल ने यह भी पुष्टि की कि कोविड–19 के मामलों में वृद्धि दक्षिण से शुरू होकर पश्चिम और अब उत्तर भारत तक पहुंच गई है। इन सभी मामलों की निगरानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के माध्यम से की जा रही है। डॉ. बहल ने कहा कि वर्तमान में संक्रमण की गंभीरता आम तौर पर हल्की है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी मामले बढ़ते हैं, तो तीन कारकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हैरू पहला वायरस की संक्रामकता, दूसरा, मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और तीसरा गंभीर मामलों का प्रतिशत। डॉ. बहल ने कहा कि वर्तमान में मामले तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और नए वेरिएंट पिछली प्रतिरक्षा को चकमा देने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश मामलों में गंभीरता कम है और सहवर्ती बीमारी वाले लोगों में ही गंभीरता देखी जा रही है। डॉ. बहल ने सतर्क रहने और तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संपादकीय

महंगी पड़ेगी सुस्ती

निस्संदेह, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी सुरक्षा उत्पादों की आपूर्ति में किसी भी लेट–लतीफी को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। खासकर ऐसे वक्त में जब देश की दो तरफ की सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियां बरकरार हैं। इसी आलोक में एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह की चिंताओं से सहमत हुआ जा सकता है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल से एक भी परियोजना तय सीमा पर पूरी नहीं होती है। निस्संदेह, यह कथन देश की स्वदेशी उत्पादों की रक्षा तैयारियों में विलंब की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। देश के नेताओं का स्वदेशी सुरक्षा उत्पादों की जरूरत पर बल देना निस्संदेह, सराहनीय कदम है, लेकिन सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर उनकी समय पर आपूर्ति भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। खासकर तेजस लड़ाकू विमान व आकाश मिसाइल प्रणाली, के बावजूद लगातार होने वाली देरी परिचालन तत्परता को बाधित करती है। निस्संदेह, लेट–लतीफी की यह प्रवृत्ति आधुनिकीकरण को पटरी से भी उतार सकती है। दरअसल, यह देरी, जो अकसर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के चरण में ही स्वीकार कर ली जाती है, कालांतर प्रणालीगत जड़ता और अति–वायदे की संस्कृति को ही उजागर करती है। हमारे पड़ोसी देशों में तेजी से होते सैन्य आधुनिकीकरण और युद्ध तैयारियों में गहन तकनीक के इस्तेमाल होने के चलते, हमें इस सुस्ती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। निर्विवाद रूप से यह महज बजट या नौकरशाही की लालफीताशाही का मामला भर नहीं है। वास्तव में यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील विषय है। निस्संदेह, सरकार की ओर से घेरलू रक्षा उत्पादकता को बढ़ावा देने की पहल एक स्वागत योग्य कदम है। विगत के संकटकाल के दौरान देखने में आया है कि युद्ध व चुनौतिपूर्ण स्थितियों में हम विदेशों में अपनी जरूरत का सामान तलाशते रहे हैं। कई देशों ने मुश्किल वक्त में सामान की आपूर्ति में ना–नुकुर भी की है। कारगिल युद्ध के समय भी कुछ ऐसे अनुभव देखने में आए थे। राजग सरकार का घरेलू रक्षा उत्पादन की तरफ बढ़ाया गया कदम निस्संदेह सराहनीय है। यह उत्साहजनक है कि हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन कुल रक्षा जरूरतों का 65 प्रतिशत हो गया है, रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। साथ ही सार्वजनिक–निजी उत्पादन का संतुलन धीरे–धीरे पक्ष में जा रहा है। वहीं आईडीईएक्स जैसी योजनाएं नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि अब निजी क्षेत्र कुल रक्षा उत्पादन में 21 फीसदी का योगदान दे रहा है। लेकिन जब जरूरी रक्षा उत्पादों की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती, तो यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता के लिये असहज स्थिति पैदा कर देती है। दरअसल, यह स्थिति इस घरेलु उद्योग की संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करने की जरूरत बताती है। इस दिशा में ध्यान देने की महती जरूरत है कि कच्चे माल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही शोध व अनुसंधान तथा विकास के लिये पर्याप्त आर्थिक संसाधन समय रहते उपलब्ध कराए जाएं। यह दृष्टव्य है कि देश के 6.81 लाख करोड़ रुपये के रक्षा बजट में मात्र 1.8 लाख करोड़ रुपये की राशि आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित की गई है।

रोजगार-आर्थिकी की राह तय करेंगे एमएसएमई

डॉ. जयंतीलाल

इन दिनों देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित रिपोर्टों में एमएसएमई की बढ़ती मुश्किलों पर टिप्पणियां करते हुए इन्हें बढ़ती चुनौतियों से बचाने की जरूरत बताई जा रही हैं। हाल ही में प्रकाशित सिडबी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी एमएसएमई के लिए सरल कर्ज की प्राप्ति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एमएसएमई की क्रेडिट

मांग व पूर्ति में 30 लाख करोड़ रुपये का अंतर है। मांग के मुताबिक लोन मिलने पर एमएसएमई के तहत 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे उद्योगों को जरूरत के मुताबिक क्रेडिट, तकनीकी कौशल तथा विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में मदद मिल जाए तो एमएसएमई रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा साधन बन सकते हैं। गौरतलब है कि एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर इस साल मार्च तक पंजीकृत 6.2 करोड़ एमएसएमई 25.95 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का योगदान करीब 30 फीसदी है। एमएसएमई से वर्ष 2024–25 में करीब 12.39 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। देश से निर्यात किए गए कुल उत्पादों में से करीब 46 फीसदी उत्पाद एमएसएमई क्षेत्र से हैं। ऐसे में भारत ने हाल ही इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किया है और अमेरिका के अलावा अन्य कई प्रमुख देशों के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के पूर्ण होने पर एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अतएव नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन देकर मजबूत बनाना जरूरी है। यद्यपि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप से टैरिफ की चुनौती के बीच अमेरिका के द्वारा भारत पर घोषित किए गए 26 फीसदी टैरिफ पर 90 दिनों के विराम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई को कुछ राहत अवश्य दी है, लेकिन अमेरिकी बाजार पर निर्भर अधिकांश एमएसएमई निर्यातक अमेरिकी खरीदारों द्वारा छूट की नई मांग और अनुबंधों पर नए सिरे से बातचीत के अलावा भुगतान में देरी जैसी चुनौतियों से अपने बचाव के लिए सरकार का रणनीतिक सहयोग जरूरी मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले माह 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि इस समय नए व्यापार युग के बदलाव के दौर में भारत के एमएसएमई के पास चुनौतियों के बीच दुनिया में आगे बढ़ने के ऐतिहासिक अवसर भी हैं और ये उद्योग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि टैरिफ वार से एमएसएमई क्षेत्र को जो झटका लग रहा है, उस झटके से एमएसएमई के उबारने के लिए जहां एक ओर सरकार के द्वारा एमएसएमई के समक्ष दिखाई दे रही चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीति बनाकर निर्यातकों को सहारा देना होगा, वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों और निर्यातकों को भी नई चुनौतियों के मद्देनजर तैयार होना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में यह बात महत्वपूर्ण है कि सरकार निर्यातकों को सहारा देने के लिए 2250 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन को तेजी से लागू करने और बिना रेहन के कर्ज दिए जाने की योजना बना रही है। साथ ही चालू वित्त वर्ष 2025–26 में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 फीसदी बढ़ाकर 17.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इसी तरह एमएसएमई क्षेत्र भी नए व्यापार युग की सच्चाइयों को समझते हुए नवाचार, प्रतिस्पर्धा, क्षमता में सुधार तथा शोध की डगर पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एमएसएमई के लिए निर्मित होने वाली विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर मौजूदा वित्त वर्ष 2025–26 के बजट में में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुआयामी उपायों की एक शृंखला प्रस्तुत की है। इसके तहत वित्तीय सहायता और खरीद नीतियों से लेकर क्षमता निर्माण और बाजार एकीकरण तक की पहलें शामिल हैं। प्रमुख पहलों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमईजीपी, स्फूर्ति और एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, रोजगार बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। उद्योगों का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए, एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ा दी गई है। निश्चित रूप से निर्यातकों को सहारा देने के सरकार के ये कदम सराहनीय हैं। लेकिन पाकिस्तान से युद्ध के माहौल और ट्रंप के टैरिफ तूफान का मुकाबला करने और निकट भविष्य में निर्मित होने वाले उभरते अवसरों को मुट्ठी में लेने के मद्देनजर एमएसएमई को हरसंभव उपाय से मजबूत बनाना होगा। नए सिरे से एमएसएमई की क्षमताओं को उन्नत करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा किसी भी निर्यात झटके से निपटने के लिए एमएसएमई को नीतिगत समर्थन का लाभ दिए जाने के प्रयासों में तेजी लाना होगी। इससे भारत की एमएसएमई उतार–चढ़ाव भरे सफर को आगे बढ़ा सकेगी। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि बुनियादी ढांचे की मजबूती, अधिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने, ब्याज समतुल्य योजना को फिर से शुरू किया जाने तथा ऋण गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार करने जैसे उपायों से एमएसएमई को वित्तीय राहत और स्थिरता प्रदान की जा सकती है। सरकार के द्वारा एमएसएमई को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के परिपालन में आ रही कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए जीएसटी व्यवस्था को सरल करना होगा। एमएसएमई के हित में उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजनाओं का विस्तार किए जाने से विशेष रूप से निर्यात–उन्मुख एमएसएमई लाभान्वित होंगे। नवाचार की नई लहर एमएसएमई के लिए नया अध्याय लिख सकती है। इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा कि भारत के एमएसएमई गुणवत्ता को मुट्ठी में लेकर समकालीन डिजिटल तकनीकों को अपनाते हुए अमेरिका सहित वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को रणनीतिक रूप से बढ़ा सकते हैं।

त्याग में अपना ही नहीं, अपनों का भी भला

कृष्ण प्रताप

यह तथ्य अब सुविदित है कि तंबाकूजन्य नशे हर साल दुनिया भर में अस्सी लाख से अधिक लोगों की जान ले लेते हैं। भारतीय होने के नाते यह और भी अधिक चिंता का विषय है कि इनमें से 13 लाख से ज्यादा मृतक भारतीय होते हैं। यह डरावना आंकड़ा न केवल चिंता उत्पन्न करता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि विविध प्रकार के तंबाकूजन्य नशों का या तो पूरी तरह उन्मूलन किया जाना चाहिए या कम से कम उन्हें न्यूनतम स्तर तक सीमित किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1988 से हर वर्ष आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में यह जानना भी प्रासंगिक है कि तंबाकूजन्य मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में इस दिवस को मनाने की परंपरा शुरू की थी। प्रारंभ में इसे 7 अप्रैल को मनाया गया, लेकिन उसी वर्ष 31 मई को संगठन द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर इसे स्थायी रूप से 31 मई को मनाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष इस दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाता है और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह भी बताया जाता है कि तंबाकू का सेवन केवल उपभोक्ता के लिए ही नहीं, बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी घातक है। विडंबना यह है कि इन प्रयासों के बावजूद विश्वभर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और वे इसकी लत से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यदि हम भारत की बात करें तो यहां तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर वैधानिक चेतावनियां प्रमुखता से अंकित की जाती हैं और अवयस्कों को इनकी बिक्री पर कानूनी रोक भी है। फिर भी, लगभग हर आयु वर्ग और लिंग के लोग इस लत के शिकार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नशा खत्म तो दूर, अपेक्षित रूप से घटता भी नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों द्वारा बार–बार यह बताया जाता है कि तंबाकू का सेवन फेफड़े, यकृत, मुंह और गर्भाशय के कैंसर के अलावा अनेक यौन और हृदय रोगों का प्रमुख कारण बन सकता है, पर इसका अपेक्षित असर होता नहीं दिखता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 38 प्रतिशत से अधिक पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं। महिलाओं में यह आंकड़ा लगभग 9 प्रतिशत है। 15 से 49 वर्ष की आयु की 1 प्रतिशत महिलाएं और 19 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैं। स्पष्ट है कि समस्या केवल तंबाकू तक सीमित नहीं, बल्कि शराब की लत भी चिंताजनक स्तर पर मौजूद है। यह निष्कर्ष देश के 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों के 707 जिलों में 6.37 लाख परिवारों के सर्वेक्षण पर आधारित है। यह बताता है कि नशे की समस्या को रोकने या सीमित करने हेतु एक दीर्घकालिक और कारगर रणनीति की आवश्यकता है, जिसका एक सिरा शिक्षा से भी जुड़ता है। क्योंकि आंकड़ों के अनुसार, भले ही तंबाकू सेवन हर वर्ग में पाया जाता है, लेकिन अशिक्षितों में इसकी प्रवृत्ति कहीं अधिक गंभीर है। स्कूल न जाने वाले या पांचवीं कक्षा से कम शिक्षा प्राप्त पुरुषों में लगभग 58 प्रतिशत और महिलाओं में 15 प्रतिशत इस लत के शिकार हैं। ग्रामीण भारत में यह समस्या और भी गहरी होती जा रही है। विशेष रूप से वंचित समुदाय इसके सबसे बड़े शिकार हैं। पूर्वोत्तर, उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में तंबाकू और अन्य नशों का प्रयोग अत्यधिक है। पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में भी स्थिति चिंताजनक है।

.... विविध ....

शुगर बोर्ड क्या है कैसे रखेगे बच्चों की चीनी पर कंट्रोल

भारत में बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन बीमारियों का एक मुख्य कारण अधिक चीनी का सेवन है जो बच्चों के दैनिक आहार में आम होता जा रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ब्ठैम्) ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय

कदम उठाया है। ब्ठैम् ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे स्कूल परिसर में 'शुगर बोर्ड' लगाएं ताकि छात्रों को अधिक चीनी सेवन से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा सके।

क्या होता है 'शुगर बोर्ड'?

'शुगर बोर्ड' एक प्रकार का सूचना प्रदर्शक (डिस्प्ले बोर्ड) है जिसे स्कूल में प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा। इस बोर्ड पर यह जानकारी दी जाएगी कि हमारे रोजमर्रा के पेय पदार्थों जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, और स्नैक्स में कितनी चीनी होती है। अधिक चीनी खाने से शरीर को कौन–कौन से नुकसान हो सकते हैं। हमें एक दिन में अधिकतम कितनी चीनी का सेवन करना चाहिए।

उदाहरणों से जागरूकता

इन शुगर बोर्ड्स पर बच्चों को रोजाना इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की चीनी की मात्रा दिखाई जाएगी जैसे

300 मिली कोल्ड ड्रिंक में लगभग 8 चम्मच चीनी होती है।

125 मिली मैंगो ड्रिंक में लगभग 5 चम्मच चीनी होती है।

1 चॉकलेट बार में औसतन 4–6 चम्मच चीनी हो सकती है।

फ्लेवर मिल्क, फ्रूट योगर्ट और पैक्ड कुकीज जैसे खाद्य उत्पादों में भी अत्यधिक चीनी होती है। इस तरह के आंकड़े बच्चों के लिए आसानी से समझने योग्य होंगे और उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे।

बच्चों में चीनी का सेवनरू चौंकाने वाले आंकड़े

4 से 10 वर्ष के बच्चों को उनकी दैनिक कैलोरी का लगभग 13: चीनी से मिलता है। 11 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए यह आंकड़ा 15: तक पहुंच जाता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (ॅभ्) के अनुसार यह सीमा 5: से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि भारतीय बच्चे अनुशंसित सीमा से लगभग 3 गुना ज्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं।

अधिक चीनी के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम

टाइप 2 – जो पहले सिर्फ वयस्कों में होती थी, अब बच्चों में भी आम हो रही है।

मोटापा – चीनी और जंक फूड के कारण बच्चों का वजन असामान्य रूप से बढ़ रहा है।

उच्च रक्तचाप – बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ना एक गंभीर संकेत है।

दांतों की सड़न– अधिक मीठा खाने से दांत कमजोर हो रहे हैं।

कमजोर इम्यून सिस्टम और थकान– अधिक चीनी ऊर्जा की जगह कमजोरी ला सकती है।

इस पहल का समर्थन कौन कर रहा है?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग – NCPCR ने भी इस अभियान का पूरा समर्थन किया है और कहा है कि यह पहल राज्य बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में भी लागू की जानी चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों में बढ़ती डायबिटीज एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थनरू प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 122वीं कड़ी में इस पहल की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा,"आपने स्कूलों में ब्लैकबोर्ड देखे होंगे लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। ब्ठैम् की यह पहल बच्चों को सेहतमंद विकल्प चुनने में मदद करेगी।"

विशेषज्ञों की राय क्या कहती है?

पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों को अगर शुरुआत से ही चीनी और जंक फूड से दूरी बनाने की आदत डाली जाए, तो वे आगे चलकर जीवनभर स्वस्थ रह सकते हैं। डायबिटोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि यह एक सकारात्मक पहल है जो टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों पर रोक लगा सकती है। बाल अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बच्चों का अधिकार है और स्कूल इस जिम्मेदारी को निभाने का सबसे अच्छा माध्यम हैं।

CBSE के निर्देश क्या कहते हैं?

CBSE ने यह स्पष्ट किया है कि,हर स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि शुगर बोर्ड प्रमुख स्थानों पर लगे हों जैसे कैंटीन, कक्षा के बाहर, मुख्य प्रवेश द्वार आदि। बोर्ड की भाषा सरल, चित्रों के साथ, और बच्चों की समझ के अनुकूल होनी चाहिए। स्कूलों को समय–समय पर छात्रों के साथ स्वास्थ्य संवाद, नुक्कड़ नाटक, और स्वस्थ आहार पर कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। अभिभावक बच्चों के खाने–पीने की आदतों पर ध्यान दें और घर में भी शुगर बोर्ड जैसे सूचना दीवारें लगाएं। बच्चे खुद जागरूक बनें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ज्यादा मीठा खाना कितना खतरनाक हो सकता है। शिक्षक और स्कूल प्रबंधन बच्चों को चीनी के अलावा स्वस्थ विकल्प जैसे फल, अंकुरित अनाज, नारियल पानी आदि के बारे में जानकारी दें।

कॉफी से चमकाएं अपनी त्वचा, Try करे ये 3 DIY फेस मास्क्स

कॉफी सिर्फ हमारी सुबह की प्यारी शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स, कैफीन और कई ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को ताजगी देने और निखारने में मदद करते हैं। अगर आपकी त्वचा डल, थकी हुई और न्यूट्रल लग रही है, तो इन कॉफी फेस मास्क को अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल करें। यहाँ तीन आसान और असरदार DIY कॉफी फेस मास्क्स दिए गए हैं, जिन्हें आप घर पर ही बना सकते हैं

कॉफी और शहद का फेस मास्क

1 चम्मच कॉफी पाउडर

1 चम्मच शहद

एक छोटी कटोरी में कॉफी पाउडर और शहद डालें। दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि पेस्ट बना जाए। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगाएं। 15–20 मिनट तक सूखने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और कोमल बनाता है। कॉफी की एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा से डलनेस को हटाती हैं और ब्राइटनेस लाती हैं।

कॉफी, दही और शहद का फेस मास्क

1 चम्मच कॉफी पाउडर

1 चम्मच दही

1 चम्मच शहद

एक कटोरी में कॉफी पाउडर, दही और शहद डालें। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करें। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। दही त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और उसे मुलायम बनाता है।कॉफी त्वचा से गंदगी और डेड सेल्स को हटाकर निखार लाती है।

कॉफी और नारियल तेल का फेस मास्क

1 चम्मच कॉफी पाउडर

1 चम्मच नारियल तेल

कॉफी पाउडर और नारियल तेल को अच्छी तरह से मिला लें।इस मिश्रण को चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं।10–15 मिनट तक छोड़ें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।नारियल तेल त्वचा को गहरी नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है।कॉफी की मदद से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और त्वचा चमकदार बनती है।

नोट

1. ये फेस मास्क हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करें।

2.पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें ताकि किसी भी एलर्जी का खतरा न हो।

3.अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है तो थोड़ी सी मात्रा में इन मास्क्स का उपयोग करें।

कॉफी का उपयोग न सिर्फ आपकी स्किन को ताजगी देता है बल्कि यह उसे ग्लोइंग और हेल्दी भी बनाता है। इन क्ष्ल कॉफी फेस मास्क्स को ट्राई करें और देखें कि आपकी त्वचा कैसे निखरने लगती है!

घर पर ही चाकू की धार तेज करने का आसान और असरदार तरीका

किसी भी किचन में चाकू का होना बहुत जरूरी है। सब्जियां और फल काटने से लेकर ब्रेड जैसे खाने की चीजों को काटने तक, चाकू का इस्तेमाल होता है। लेकिन अच्छे से काटने के लिए चाकू का तेज यानी शार्प होना भी बहुत जरूरी है। अगर चाकू की धार कमजोर हो जाए तो काटना मुश्किल हो जाता है और खाना बनाना भी कठिन हो सकता है।

चाकू की धार क्यों कम हो जाती है?

लगातार चाकू के इस्तेमाल और सही तरीके से रखरखाव न करने की वजह से उसकी धार जल्दी कम हो जाती है। इसके अलावा, अगर चाकू को सही जगह नहीं रखा जाए या गलत सतह पर इस्तेमाल किया जाए, तो भी उसकी धार खराब हो सकती है। इससे फल और सब्जियां ठीक से नहीं कटतीं और हाथ में जख्म लगने का खतरा भी रहता है।

महंगे चाकू और उनकी देखभाल की समस्या

अगर आपका चाकू महंगा हो तो बार–बार नया चाकू खरीदना सही नहीं होता। महंगे चाकू को बार–बार बदलना भी महंगा और मुश्किल काम होता है। वहीं सस्ते चाकू को बार–बार खरीदना भी समय और पैसे की बर्बादी है। दुकान पर चाकू की धार तेज करवाई जा सकती है लेकिन इसके लिए दुकान पर जाना पड़ता है और समय निकालना होता है जो हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए बेहतर होगा कि घ घर पर चाकू तेज करने के लिए जरूरी सामान

घर पर चाकू की धार तेज करने के लिए आपको बस कुछ आम चीजें चाहिएरू

टूथपेस्ट

नमक

सिरेमिक कप

शिप्रा राय की ।

प्रदेश में आज से दिखेगा नौतपा का असर, घटेगा बारिश और आंधी का दायरा इन जिलों में छाए रह सकते हैं बादल

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में मौसम एक बार फिर से गर्म होना शुरू हो गया है। शनिवार को आगरा सहित कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर गया। लखनऊ में व बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दायरा घटेगा। वहीं प्रदेश में शनिवार को आगरा में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे

उमस भरी गर्मी थी। रात में उमस होने की वजह से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश में बारिश और आंधी का दायरा कम होगा। हालांकि रविवार को भी पूर्वी व पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंधी व बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी गर्म रहा। वहीं उरई में 41.8, बहराइच में 41.6, मुरादाबाद में 41.5 और और वाराणसी में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

धरे रह गए पूर्वानुमान, पसीने में बह गईं राहत की उम्मीदें

मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले लखनऊ में शुक्रवार रात से बादल छाने और शनिवार को छिटपुट बारिश के आसार जताए थे। भीषण उमस से परेशान लखनऊ के लोगों के लिए यह खबर राहत की सौगात लिए थी। शनिवार को सभी पूर्वानुमान धरे रह गए। तीखी धूप के बीच 40 डिग्री तापमान में भीषण उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। बेहिसाब पसीने में राहत की उम्मीदें भी बह गईं।

मौसम विभाग ने अब एक बार फिर लखनऊ व आस–पास के जिले के लोगों को अगले दो दिन भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार रविवार को आसमान में बदल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। सोमवार को बारिश के आसार बन रहे हैं। इधर, शनिवार को काफी दिनों के बाद लू भी महसूस की। तपिश बढ़ने से अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री बढ़ोत्तरी के साथ 40.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री की गिरावट के साथ 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे जिससे तेज धूप से राहत मिलेगी, जबकि सोमवार को बारिश होने का अनुमान है। लखनऊ के आस–पास के जिलों में भी चमक–गरज के साथ बारिश हो सकती है।

सीट घोषित हुई रिक्त, छुट्टी के दिन खुला सचिवालय... चुनाव आयोग को भेजी गई सूचना

लखनऊ, (संवाददाता)। हेट स्पीच केस में सजा के एलान के बाद यूपी के मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इसके लिए रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया। चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है। अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत कुल 11 का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद

गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।

सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी

आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा हिसाब–किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।

इस मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। धारा 120बी भादवि के तहत उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

संक्षिप्त समाचार

डीजीपी पद पर नहीं हुआ सेवा विस्तार, पर मिल सकता है कोई अहम पद

लखनऊ, (संवाददाता)। डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए प्रशांत कुमार का 14 माह का कार्यकाल माफिया व अपराधियों को धूल चटाने वाला रहा। उन्होंने महाकुंभ, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह समेत कई बड़े आयोजनों में पुलिस के आतिथ्य सत्कार की नई मिसाल पेश कर धाक भी जमाई। भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में मेरठ जोन का एडीजी रहने के दौरान उन्होंने पश्चिमी यूपी के तमाम कुख्यात अपराधियों का सफाया कराया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एडीजी कानून व्यवस्था बना दिया। उन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया और उनके गैंग के सदस्यों की कमर तोड़ी, तो सीएम ने उनको 31 जनवरी 2024 को डीजीपी बना दिया। शनिवार को सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कई पूर्व डीजीपी की परंपरा का पालन किया और रैतिक परेड जैसी औपचारिकताओं से दूर रहे। सीएम के भरोसेमंद अफसर होने की वजह से उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है। राजीव कृष्णा पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। राज्य सरकार ने उनको डीजीपी पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इसके लिए उन्हें कोई अलग वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को डीजीपी नियुक्त किया है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्ण 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर डीजीपी बनाए गए हैं। बता दें कि निवर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिल सका, जिसके बाद देर शाम राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने रात करीब 9 बजे डीजीपी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि मूल रूप से गौतमबुद्धनगर के निवासी राजीव कृष्णा इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है।

यूपी में खसरा–रुबेला का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में आज से खसरा– रुबेला (एमआर) टीकाकरण विशेष अभियान शुरू हो रहा है। जिन बच्चों को यह टीका नहीं लगा है, उनकी जान को खतरा है। यह टीका लगवाकर इन बच्चों को तमाम बीमारियों से बचाया जा सकता है। उनकी जान का खतरा भी कम किया जा सकता है। यही वजह है कि विभाग की ओर से कम टीकाकरण वाले 12 जिलों के 205 ब्लॉक में एक–एक बच्चे की निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2026 तक खसरा– रूबेला मुक्त करने की लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत एक जून से 30 जून तक एमआर टीकाकरण विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। सामान्य तौर पर नौ माह पूरा होने पर खसरा– रुबेला का पहला टीका (एमआर 1) और 16 माह पूरा होने पर दूसरा टीका (एमआर 2) लग जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में टीकाकरण प्रभावित हुआ। ऐसे में अब विशेष अभियान के तहत पांच साल तक के उन सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, जो अभी तक छूटे हुए हैं। मालूम हो कि इससे पहले नवंबर–दिसंबर 2024 में 305 ब्लॉकों में अभियान चलाकर छूटे हुए ।

हेल्पलाइन नंबर 1912 पर सुबह से बिजली उपभोक्ताओं की सुनवाई बंद

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लखनऊ समेत 19 जिलों के उपभोक्ताओं की रविवार सुबह से बिजली शिकायतों की सुनवाई बंद हो गई है। यह संकट लखनऊ के हुसैनगंज स्थित 1912 काल सेंटर में तकनीकी खामी आने से उत्पन्न हुआ है। इससे उपभोक्ताओं की बिजली संकट की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है । हालांकि, इस तकनीकी खामी को दूर करने के लिए बीएसएनएल टीम रविवार सुबह आठ बजे से जुटी है। मध्यांचल निगम के एक अफसर ने बताया कि लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव ,हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत जिलों के उपभोक्ताओं की सुनवाई न होने पर उनकी सहूलियत के लिए 1912 काल सेंटर की सेवा उपलब्ध कराई गई थी। अफसर ने बताया कि इस नंबर पर रविवार सुबह सात बजे से उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज नहीं हो पा रही है। उपभोक्ता काल करते, मगर रिसीव नहीं हो रही है। इस पर दर्ज कराएं शिकायतें

गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने बताया कि उपभोक्ताओं ने शिकायत कर 1912 पर शिकायत दर्ज न होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं की जब तक 1912 पर शिकायतें दर्ज नहीं हो रही तब तक व्हाट्सप्प नंबर , ई–मेल, कंज्यूमर एप पर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

अनियंत्रित होकर पलटा बालू लदा ट्रक, नीचे दबने से महिला की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के श्रावस्ती में रविवार को मवेशियों को बचाने के प्रयास में बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि उसका पुत्र व दामाद का भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से बालू व ट्रक को हटवाकर शव को बाहर निकलवाया। घायलों को मेडिकल कॉलेज बहराइच ले जाया गया। हादसा सोनवा क्षेत्र के बदला–बरदेहरा मार्ग पर धूम बोझी के निकट हुआ। भिनगा नगर निवासी शमीम की पुत्री का विवाह गिरंट बाजार निवासी रिजवान से हुआ है। रविवार को रिजवान का भाई सुफियान (20) भिनगा आया

था। यहां से वह अपने भाई की सास कमरुल निशा (40) व भाई शमीम (8) को लेकर बाइक से गिरंट बाजार जा रहा था। रास्ते में मथुरा प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धूम बोझी के पास बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान कमरुल निशा, सुफियान व तौहीद ट्रक के नीचे आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से बालू व ट्रक हटवाकर

तीनों को बाहर निकाला। इस दौरान कमरुल निशा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूफियान व तौहीद की हालत गंभीर होने के कारण है।

संक्षिप्त समाचार

अब सड़े–गले नोटों से होगी इंटीरियर डिजाइनिंग, बनेंगे फर्नीचर आरबीआई ने दी हरी झंडी

लखनऊ, (संवाददाता)। प्लास्टिक से लेकर लकड़ी और धातुओं के फर्नीचर तो बाजार में बहुत हैं, लेकिन अब नोट (करेंसी) से बने पार्टिकल बोर्ड के फर्नीचर भी दिखेंगे। कटे–फटे और सड़े–गले नोटों से बने रंग–बिरंगे बोर्ड तैयार करने पर रिजर्व बैंक काम कर रहा है। इसके तहत नष्ट किए गए नोटों को लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर पार्टिकल बोर्ड तैयार किया जाएगा। इस बोर्ड का इस्तेमाल फर्नीचर सहित अन्य कामों में किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बैंकनोट पेपर में सुरक्षा धागे, फाइबर, सुरक्षा स्याही और छपाई में इस्तेमाल अन्य रसायनों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक को करेंसी के निपटान के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान की तलाश थी। इसके लिए एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को आरबीआई ने अब लागू करने का फैसला किया है। पिछले कुछ वर्षों में, आरबीआई हर वर्ष 15 हजार टन सड़े–गले नोट को नष्ट करता है। करेंसी को नष्ट करने के लिए विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक व प्राधिकरण फिलहाल अलग–अलग तरीके अपनाते हैं। इनमें से अधिकांश जमीन में गाड़ने या जलाते हैं। लेकिन, ये तरीके पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं क्योंकि ये मिट्टी को प्रभावित कर सकते हैं या पर्यावरण को खराब कर सकते हैं। अध्ययन में सड़े–गले बैंकनोट से तैयार उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही टिकाऊ भी पाए गए हैं। इनसे लंबे समय तक चलने वाली सामग्री जैसे बोर्ड पैनल, इंटीरियर डिजाइन के लिए सामग्री, पार्टिकल बोर्ड फर्नीचर आदि बनाया जा सकता है।

डिप्टी सीएम को देख चिल्लाए मरीज, साहब–बाहर की दवाएं लिखते हैं यहां के डॉक्टर

लखनऊ, (संवाददाता)। सुबह 10.52 पर यूपी के सीतापुर के जिला अस्पताल गेट पर डीएम व एसपी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का इंतजार कर रहे थे। दो मिनट बाद डिप्टी सीएम का काफिला पहुंचा तो अफसर अलर्ट हो गए। डिप्टी सीएम पर्चा काउंटर पर लगी लाइन देखकर सीधे मरीजों के बीच पहुंच गए। सीएमएस ने पूछा कितने काउंटर है तो बोले सर तीन.. तो वह मैनपॉवर खिड़की छाककर गिरने लगे। सीएमएस से कहा भीड़ बहुत है इसलिए कम से कम पांच काउंटर बनाएं। मरीज जोर से चिल्लाएं साहब बाहर से दवा लिखी जाती है। एक रुपये का पर्चा 50 रुपये में बनता है। इससे डिप्टी सीएम बेहद नाराज दिखे। ऐसी समस्या कई मरीजों ने बताई। करीब 10 मिनट मरीजों से बात करने के बाद सीधे वह इमरजेंसी कक्ष की तरफ पहुंचे तो आंख उठाकर ऊपर देखी तो एक्जॉस्ट फैन का केवल फेम लगा था। सीएमएस से कहा पंखा कहां है तो वह नहीं बता पाए। गेट के पास ही अग्निशमन सिलिंडर लगा था। इस पर एक्सपायर्ड तिथि अंकित थी तो दूसरी पर नहीं थी। मंत्री ने कई बार सिलिंडर इधर–उधर घुमाया, लेकिन डेट नहीं दिखी। प्रभारी मंत्री मंयकेश्वर शरण सिंह भी सिलिंडर पलटते रहे। उसके बाद इमरजेंसी में अंदर जाकर मरीजों से हालचाल लिया। 10 मिनट बाद वह इमरजेंसी भर्ती कक्ष में पहुंचे तो एसी देखी तो वह बंद मिली। सीएमएस से पूछा यह कैसे बंद है तो सीएमएस सिस्टर–सिस्टर कहकर आवाज लगाने लगे। लेकिन जवाब नहीं दे पाए। इसी वार्ड में भर्ती एक बच्चे को देखकर कहां कि इसे चिल्ड्रेन वार्ड में भर्ती कराओ। 15 मिनट बाद वह मीटिंग के लिए आयुष कक्ष की तरफ निकले तो पैथालॉजी का इमरजेंसी गेट बंद था।

अधिकारियों की वजह से अटके एडेड कॉलेज में ऑनलाइन तबादले, आर्थिक शोषण के आरोप

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से लगभग हर छोटे–बड़े काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। वर्तमान तबादला सत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन तबादलों के लिए आदेश जारी कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) कॉलेजों के शिक्षकों के तबादलों के लिए मानव संपदा पोर्टल को प्रभावी किया गया है। हर साल गर्मी की छुट्टियों में होने वाले तबादले की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाती है। किंतु 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों के 60 हजार से अधिक शिक्षक अभी भी इससे वंचित हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि पूर्व में तबादले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने का आदेश भी जारी किया जा चुका

लिए अभी भी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। प्रदेश में शिक्षकों–कर्मचारियों को मानसिक व आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही विभिन्न विभागों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी सेवा संबंधित सभी मामलों, छुट्टियों, तबादलों, नियुक्ति, एसीपी आदि के है। किंतु अभी तक इसे प्रभावी नहीं किया गया है। इस पर विभागीय अधिकारी कुंडली मारके बैठे हुए हैं। पिछले साल भी ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया अपनाई गई। शिक्षक विधायकों ने विधान परिषद में भी इससे जुड़ा मुद्दा उठाया था। शिक्षकों ने कहा कि विभाग जहां पद खाली हैं, वहां का ब्योरा ऑनलाइन कर, उस पर शिक्षकों से आवेदन लेकर तबादला करे।

शिक्षकों का आरोप है कि जिस विद्यालय से तबादला होना है और जहां तबादला लेना है, उसकी एनओसी के लिए से लेकर तैनाती तक में आर्थिक शोषण हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रभावी करना अनिवार्य है। साथ ही अगर शिक्षक के सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे हैं तो एक निर्धारित समय में एनओसी जारी करने का भी आदेश जारी किया जाना चाहिए। तभी पारदर्शी तरीके से तबादला प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

हो एनओसी विहीन तबादला

एडेड कॉलेजों में एनओसी विहीन तबादला किया जाना चाहिए। एनओसी देने के लिए प्रबंधन से लेकर विभागीय अधिकारियों समेत कुल नौ जगहों पर जेब गर्म करनी पड़ती है। ऑफलाइन तबादले बंद करके ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। संजय द्विवेदी, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ

अगले सप्ताह तक एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के लिए तबादला प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे भी ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारी चल रही है। शिक्षकों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका प्रयास किया जाएगा

11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर मिली राजीव कृष्णा को तवज्जो, इसलिए बनाया गया यूपी पुलिस का मुखिया

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को डीजीपी नियुक्त किया है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्ण 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर डीजीपी बनाए गए हैं। बता दें कि निवर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिल सका, जिसके बाद देर शाम राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने की घोषणा कर दी है। बता दें कि मूल रूप से गौतमबुद्धनगर के निवासी राजीव कृष्णा इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है। उन्हें दो बार राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी चार वर्ष और एक माह का समय बाकी है, जिसकी वजह से वह लंबे समय तक प्रदेश के डीजीपी बने रह सकते हैं। दरअसल, प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार ने राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराई, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत का लोहा मानते हुए राज्य सरकार ने उन्हें प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाने का फैसला लिया है। राजीव कृष्णा लखनऊ समेत कई जिलों के पुलिस कप्तान भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह लखनऊ के एडीजी जोन भी रहे हैं। उनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी हैं और लखनऊ स्थित

आयकर विभाग के मुख्यालय में तैनात हैं। वर्ष 1989 बैच के शफी अहसान रिजवी, आशीष गुप्ता, आदित्य मिश्रा, वर्ष 1990 बैच के संदीप सालुंके, दलजीत सिंह चौधरी, रेणुका मिश्रा, बिजय कुमार मौर्य, एमके बशाल, तिलोत्तमा वर्मा, वर्ष 1991 बैच के आलोक शर्मा और पीयूष आनंद। राजीव कृष्णा लखनऊ, मथुरा, इटावा, आगरा और नोएडा समेत कई जिलों के पुलिस कप्तान भी रह चुके हैं। इटावा में तैनाती के दौरान उन्होंने दस्युओं के गिरोह का सफाया भी किया था इसके अलावा वह लखनऊ के एडीजी जोन और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बार्डर सिक्योरिटी फोर्स में आईजी ऑपरेशन भी रहे हैं। यूपी में एटीएस के गठन में भी उनकी अहम भूमिका थी। उनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी हैं और लखनऊ स्थित आयकर विभाग के मुख्यालय में तैनात हैं।

प्रशांत को नहीं मिला विस्तार

शनिवार को पूरे दिन प्रशांत कुमार का सेवा विस्तार होने की अटकलें लगती रहीं। देर शाम तक प्रशांत कुमार द्वारा डीजीपी पद का कार्यभार नहीं छोड़ने पर इन अटकलों को बल मिलता गया, हालांकि रात करीब आठ बजे राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने की घोषणा कर दी गई। देर शाम प्रशांत कुमार, राजीव कृष्णा और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर उन्हें पुलिस विभाग की ।

नए डीजीपी पर अखिलेश यादव ने की टिप्पणी, दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई जनता क्यों झेले

लखनऊ, (संवाददाता)। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सेवानिवृत्त हुए डीजीपी प्रशांत कुमार का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए कहा कि वे जाते–जाते जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला, जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम–से–कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अखिलेश ने एक्स के माध्यम से कहा कि अब देखना ये है कि वे जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं, नये वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के मायाजाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली–लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता क्यों झेले। जब डबल इंजन (सरकार) मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश–प्रदेश क्या चलाएंगे। उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी मिलने पर कटाक्ष किया।

राजीव कृष्णा ने ग्रहण किया कार्यभार

प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को डीजीपी नियुक्त किया है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति

बोर्ड के अध्यक्ष के साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्ण 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर डीजीपी बनाए गए हैं। बता दें कि निवर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिल सका, जिसके बाद देर शाम राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने रात करीब 9 बजे डीजीपी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि मूल रूप से गौतमबुद्धनगर के निवासी राजीव कृष्णा इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है। उन्हें दो बार राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड समेत कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी चार वर्ष और एक माह का समय बाकी है, जिसकी वजह से वह लंबे समय तक प्रदेश के डीजीपी बने रह सकते हैं। दरअसल, प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार ने राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराई, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत का लोहा मानते हुए राज्य सरकार ने उन्हें प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाने का फैसला लिया है।

लगातार पांचवी बार कार्यवाहक डीजीपी

बता दें कि राजीव कृष्णा प्रदेश के पांचवें कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। इससे पहले डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार, प्रशांत कुमार कार्यवाहक बनाए गए थे। इसकी वजह राज्य सरकार द्वारा बीते करीब तीन वर्ष से संघ लोक सेवा आयोग को पैनल नहीं भेजा जाना है।

मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ द्वारा प्रयागराज में यूरोलॉजी और हीमैटो–ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

प्रयागराज। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ ने प्रयागराज स्थित द्वारका हॉस्पिटल में यूरोलॉजी और हीमैटो–ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। यह सेवाएं हर माह के तीसरे गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। अब यूरोलॉजी या रक्त सम्बंधी समस्याओं के लिए प्रयागराज और आस–पास के लोगों को दूर नहीं जाना होगा। इस अवसर पर डॉ. अदित्य के. शर्मा, निदेशक यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक यूरो–ऑन्कोलॉजी तथा डॉ. दीपांकर भट्टाचार्य, वरिष्ठ सलाहकार, मेडिकल एवं हीमैटो–ऑन्कोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ, उपस्थित रहे। ओपीडी सेवाओं की शुरुआत के दौरान डॉ. अदित्य के. शर्मा, निदेशक यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक यूरो–ऑन्कोलॉजी, ने कहा कि आज की बदलती जीवनशैली का गुर्दों की सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग अक्सर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब स्थिति गंभीर हो जाती है तभी चिकित्सकीय सहायता लेते हैं। इस ओपीडी के माध्यम से हमारा लक्ष्य किडनी स्टोन, प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं, यूरिनरी ट्रैक्ट का संक्रमण, ब्लैडर पर नियंत्रण न होने की परेशानी और पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए प्रारंभिक परामर्श प्रदान करने का है। इससे प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ उपचार उनके निकट ही उपलब्ध हो सकेगा।

डॉ. दीपांकर भट्टाचार्य, वरिष्ठ सलाहकार, मेडिकल एवं हीमैटो–ऑन्कोलॉजी, ने कहा कि हीमैटोलॉजिकल यानी खघून संबंधी बीमारियां कई बार तब तक सामने नहीं आतीं जब तक वह गंभीर रूप न लेतीं। हमारा उद्देश्य है कि मरीजों को इन बीमारियों से जुड़ी शुरुआती जांच व रोकथाम की सुविधा मिले, ताकि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। खघून से जुड़ी बीमारियां शरीर को बहुत गहराई तक प्रभावित कर सकते हैं और इनका समय रहते इलाज बेहद जरूरी होता है। इस ओपीडी सेवा के माध्यम से हम इन रोगों की समय पर पहचान और प्रबंधन की दिशा में काम करेंगे। मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ की यह पहल प्रयागराज क्षेत्र में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाएगी।

सभी को अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए : आनंदी बेन

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरदोई पहुँचीं। लखनऊ से वह हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन ग्राउंड पहुँचीं। यहाँ से राज्यपाल जिला कारागार पहुँचीं। यहाँ उन्होंने नव स्थापित वाटर कूलर का फीता काटकर उदघाटन किया। महिला बैरक में उन्होंने महिला कैदियों से खाने की गुणवत्ता व अन्यथा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वाटर कूलर से ठंडा पानी पियें। पानी को बिल्कुल बर्बाद न करें। उन्होंने प्रशिक्षण केन्द्र में सिलाई प्रशिक्षण को देखा। उन्होंने बैरक के अस्पताल को देखा। इसके पश्चात उन्होंने महिला कैदियों के बच्चों की शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लास की व्यवस्था देखी। तत्पश्चात उन्होंने परिसर में महिला बंदियों व माध्यमिक विद्यालयों की बच्चियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अनुशासन सीखना चाहिए। उन्होंने जेल में आधुनिक व जैविक खेती की सराहना की। उन्होंने बच्चियों से जेल भ्रमण के अनुभवों पर निबंध लिखकर राजभवन प्रेषित करने को कहा। उन्होंने बंदियों से कहा कि मन में बदले का भाव न रखें। आगे एक अच्छा जीवन बिताएं। विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने महिला कैदियों व उनके बच्चों को उपहार दिए। राज्यपाल महोदया द्वारा जेल अधीक्षक को कुछ पुस्तके भेंट की गयीं। जिलाधिकारी अनुनय झा ने राज्यपाल महोदया का आभार जताते हुए कहा कि सभी लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद 9 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चियों का एचपीवी टीकाकरण करा लिया जाएगा। जिला कारागार से राज्यपाल महोदया स्टेटस क्लब पहुँचीं। यहाँ उन्होंने विभिन्न विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्टेटस क्लब हॉल के अंदर कार्यक्रम के प्रारम्भ से पूर्व राज्यमंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, विधायक सवायजपुर माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, विधायक संडीला अलका सिंह अर्कवंशी, जिलाध्यक्ष भाजपा अजीत सिंह बब्बन व अन्य माननीय जन प्रतिनिधियों ने राज्यपाल महोदया का पुष्प देकर स्वागत किया। जिलाधिकारी अनुनय झा ने जनपद के आँगनबाड़ी केंद्रों की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने शिशुओं, धात्री महिलाओं व कुपोषित बच्चों के लिए किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में जनपद के आँगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर एक वीडियो क्लिप भी दिखाई गयी।कार्यक्रम की शुरुआत आँगनबाड़ी केन्द्र फर्दापुर की बच्चियों ने सरस्वती वंदना के साथ की। इस बाद पाँच वर्ष के धैर्य ने शिवतांडव स्त्रोत सुनाकर माननीय राज्यपाल महोदया को प्रभावित किया। राधा नगर आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों ने देश भक्ति आधारित गीत पर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। प्राथमिक विद्यालय सनफरा के बच्चों का प्रदर्शन देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। प्राथमिक विद्यालय फिरोजापुर की बच्चियों ने जिस प्रकार गाने के माध्यम से व्याकरण समझाई उसने सभी को प्रभावित किया। राज्यपाल महोदया ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने बच्चों को गिफ्ट पैक भेंट किया। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक छात्रा निष्ठा शुक्ला ने विकसित भारत पर आधारित ओजपूर्ण भाषण देकर सभी को बांधे रखा।अपने सम्बोधन में राज्यपाल महोदया ने अपने सम्बोधन में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। आँगनबाड़ी केंद्र से लेकर उच्च शिक्षा तक एक सततता होनी चाहिए जिससे विकसित भारत का सपना साकार हो सके। हमारे देश व प्रदेश में इस दिशा में कार्य हो रहा है। महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा लिंगानुपात को बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिए। बेटी को बचाने के लिए कार्य होना चाहिए। बेटी का अच्छी तरह से पालन पोषण होना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बेटियां आज सब कुछ कर सकती हैं। सभी को अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। कौशल का विकास होना चाहिए। उन्होंने आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों की उनके योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने दहेज की चर्चा करते हुए कहा कि दहेज अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है। इसको बन्द करने की जरुरत है।सास को बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। भारत भर में नारी सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा। अब हमारी बेटियां बाहर निकल सकती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं।

श्री कृष्ण दत्त एकेडमी (डिग्री कॉलेज) में फाइन आर्ट्स वर्कशॉप का शुभारंभ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। श्री कृष्ण दत्त एकेडमी (डिग्री कॉलेज), वृंदावन योजना, लखनऊ के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (बी.एफ.ए.) विभाग द्वारा दिनांक 2 जून 2025 को फाइन आर्ट्स वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला 7 जून 2025 तक चलेगी और इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। कार्यशाला में कैनवास पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, डिजिटल पेंटिंग और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। यह रचनात्मक कार्यशाला उभरते कलाकारों, कला शिक्षकों और रचनात्मक सोच रखने वालों को एक मंच पर लाकर, विभिन्न कला रूपों के अनुभव, व्यावहारिक प्रशिक्षण और विचारों के आदान–प्रदान का अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री कृष्ण दत्त एकेडमी की आर्ट गैलरी में दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में सहायक निदेशक (शैक्षणिक) कुसुम बत्रा, पार्षद द्रोपदी रावत (सरोजिनी नगर), प्राचार्या प्रो. सुमन गुप्ता (महाराजा बिजली पासी कॉलेज), प्राचार्या रश्मि शर्मा (गौतम बुद्ध डिग्री कॉलेज), प्रबंधक विवेक सिंह (सर्वांगीण विकास) तथा मां विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज, नीलमथा से वीरेंद्र यादव उपस्थित रहे। कॉलेज के प्राचार्य नवीन कुमार कुलश्रेष्ठ ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में रचनात्मक शिक्षा और इस प्रकार की कार्यशालाओं की युवाओं के कलात्मक विकास और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में भूमिका को रेखांकित किया। एस.के.डी. ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक श्री मनीष सिंह ने भी कार्यशाला की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित कीं और बी.एफ.ए. विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए इसे शिक्षा का एक अहम हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। यह सप्ताह भर चलने वाला आयोजन इंटरैक्टिव सत्रों, विशेषज्ञों द्वारा डेमो और नवोदित कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। कॉलेज ने सभी योग्य प्रतिभागियों से इस रचनात्मक अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

रिटायर्ड जिला युवा कल्याण अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या शव सड़क किनारे बरामद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार सुबह एक रिटायर्ड जिला युवा कल्याण अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। खुटहन थाना क्षेत्र के गैरवाह गांव निवासी राम कृपाल यादव का शव लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहे पर स्थित एक रेस्टोरेंट के सामने मिला। ये वर्तमान में शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे के निकट कृषि ऑफिस के सामने स्थित सुंदर नगर कॉलोनी में निवास कर रहे थे। रविवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राम कृपाल यादव जौनपुर से युवा कल्याण अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच–पड़ताल शुरू कर दी है। घटनास्थल की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके से कुछ चीजें बरामद किया है।इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है । सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी से मृतक को ले जाते मिलने पर उसी कालोनी से एक महिला और आदमियों को गिरफ्तार कर मामले की पूछताछ की जा रही है।

लखनऊ की ओर जा रही प्राइवेट बस मारुति वर्कशॉप में घुसी,गार्ड की मौत

अयोध्या। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर बस्ती से लखनऊ की ओर तीव्र गति से जा रही एक प्राइवेट बस थाना कैंट क्षेत्र के कोटसराय के पास मारुति वर्कशॉप की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गई।जिसके चलती वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा।वही वहां पर मौजूद कुछ लोग इधर–उधर भागने लगे।इस हादसे में मारुति वर्कशॉप पर तैनात गार्ड की मौत हो गई।वही बस में बैठे यात्री इस हादसे में बाल बाल बच गए।इस हादसे की सूचना पाते ही सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह,थानाध्यक्ष कैंट पंकज पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच पर पहुंच कर बचाव कार्य में जुट गए। इस संबंध में थानाध्यक्ष करंट पंकज सिंह ने बताया के रविवार को दोपहर बाद बस्ती से लखनऊ की ओर एक प्राइवेट बस तीव्र गति से जा रही थी। जब वह थाना कैंट क्षेत्र के कोट सराय स्थित मारुति वर्कशॉप की समीप पहुंची तभी अनियंत्रित होकर उक्त कर्मी साहब की दीवाल तोड़ते हुए अंदर घुस गई। बताया कि इस हादसे में मौके पर मौजूद गार्ड की मौत हो गई। गनीमत इस बात की राही इस हादसे में किसी बस यात्री तथा वहां पर मौजूद अन्य लोगों को कोई चोट नहीं आई। बताया कि फिलहाल पुलिस इस मामले में हादसा करने वाले प्राइवेट बस को अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही करने में जुटी हुई है।

02 जून को जनपद भ्रमण पर रहेंगी राज्यपाल आनंदी बेन

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) राज्यपाल आनंदी बेन पटेल कल 02 जून को जनपद भ्रमण पर आएंगी। सुबह 9:34 बजे जिला कारागार पहुंचेंगी। 9:37 बजे महिला बैरक का भ्रमण कर कैदियों के साथ संवाद करेंगी। 9:50 बजे जीजीआईसी की बालिकाएं स्वागत गीत पेश करेंगी। 9:55 बजे महिला कैदियों व उनके बच्चों को सामग्री वितरित करेंगी। 10 बजे माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं से संवाद करेंगी। 10:10 बजे विचार व्यक्त करेंगी। इसके बाद स्टेटस क्लब पहुंचेंगी। उनके आगमन को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

काशी एक्सप्रेस ट्रेन मे बंम की सूचना पर हलकान पुलिस, हो रही जांच

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,। मीरगंज थाना अंतर्गत गोरखपुर से कुर्ला जाने वाली 15018 काशी एक्सप्रेस ट्रेन मे बंम की सूचना पर जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को खडा करके चेकिंग की गयी फिलहाल एक घंटे तक मीरगंज पुलिस आरपीएफ, जीआरपी ने चेकिंग अभियान चलाया पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बंम निरोधक दस्ता को प्रयागराज व जौनपुर से बुलाया गया है ट्रेन एक घंटे से जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खडी है।

किसी ने फोन रेलवे कन्ट्रोल को सूचना दिया की स्लीपर बोगी एस–1से से एस–4 मे किसी मे बैग मे बंम रक्खा गया है। कन्ट्रोल ने तत्काल इसकी सूचना जीआरपी और जंघई स्टेशन प्रसाशन को दिया सूचना मिलते जैसे ही ट्रेन जंघई ट्रेन जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर तीन बजकर दो मिनट पर पहुची। आरपीएफ इन्सपेकटर आलोक तिवारी एसआई नागेन्द्र सिंह जीआरपी प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा तथा थानाध्यक्ष मीरगंज विनोद अंचल एसआई मुन्नी लाल मौके पर पहुँच गये और ट्रेन की सभी बोगियों को कई बार चेकिंग लेकिन कुछ मिला नही, इस दौरान पुलिस हलकान रही ट्रेन लगभग दो घंटे से जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खडी है बंम निरोधक दस्ता को प्रयागराज से बुलाया गया है बंम निरोधक दस्ता के आने के बाद ट्रेन की फिर चेकिंग की गयी बंम निरोधक दस्ता के अनुमति के बाद ट्रेन को चलाया जायेगा।

स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह का कहना है की बंम की सूचना पर काशी एक्सप्रेस ट्रेन को जंघई रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कराई गयी फिलहाल कुछ नहीं मिला है बंम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है।

योग भारत की प्राचीनतम धरोहर : प्रो. वंदना सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। ।वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में सोमवार को मुक्तांगन परिसर में ष्सूर्य नमस्कारष पर आधारित विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह के नेतृत्व में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार और विविध योगासन का अभ्यास किया। कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम धरोहर है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। उन्होंने सूर्य नमस्कार को योग की एक अत्यंत प्रभावशाली श्रृंखला बताते हुए कहा कि यह अभ्यास सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए शरीर, मन और आत्मा का समन्वय स्थापित करता है। कुलपति प्रो सिंह ने प्रतिभागियों को योग को जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश देते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और योग प्रशिक्षक जय सिंह द्वारा प्रतिभागियों को सूर्य नमस्कार की बारह शारीरिक क्रियाओं के साथ–साथ विभिन्न योगासन व प्राणायाम की विधियां अभ्यास पूर्वक कराई गईं। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ योग सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर कुलसचिव महेंद्र कुमार, कार्यक्रम संयोजक एवं छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. प्रमोद कुमार यादव, प्रो. विक्रम देव शर्मा, प्रो. राजकुमार, प्रो. गिरिधार मिश्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ. राजबहादुर यादव, उपकुलसचिव अमृत लाल, डॉ. रसिकेश, डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय सहित विभिन्न संकायों के शिक्षकगण, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

किायाश हेल्थ क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर" का मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज दिनांक 01 जून 2025 को "कियाश हेल्थ क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर" का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार युवा एवं खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा उनके कर–कमलों से किया गया। इस अवसर पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि यह केंद्र क्षेत्रवासियों को अत्याधुनिक जांच व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ डॉ. रिमी (एम.डी.) द्वारा आधुनिक जाँच सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी तथा डॉ. अभिषेक मौर्य (एम.डी.) हृदय रोग एवं मधुमेह जैसे गंभीर रोगों का उच्चस्तरीय उपचार प्रदान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, ष्यह क्लिनिक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद बनेगा, जहाँ मरीजों को अब बड़े शहरों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।ष्कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री का सुरेंद्र कुमार मौर्य, पंकज मौर्य, एवं आरएसएस के काशी प्रांत के सह सामाजिक समरसता संयोजक शिव प्रकाश मौर्य द्वारा पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत किया गया।

अलग–अलग थाना क्षेत्र में हुए पुलिस मुठभेड़ में एक को तस्कर पैर में लगी गोली,तीन गिरफ्तार

घायलों को सीएससी और जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, अपराधियों पर विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमा है दर्ज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों, लाइन बाजार खेतासराय, जलालपुर में रविवार देर रात हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर समेत तीन अपराधियों के पैर में लगी गोली पुलिस ने सभी को किया गिरफ्तार इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती कराया है जहां इनका इलाज चल रहा है। खेतासराया थाना अंतर्गत मनिकलां के पास चेकिंग के दौरान क्षेत्राधिकार शाहगंज अजीत सिंह चौहान द्वारा चेकिंग के दौरान खेतासराय पुलिस टीम के साथ बाइक सवार बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में दोनो तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली मौके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार।पकड़े गए बदमाश मनीष यादव के पास से पुलिस ने एक तमंचा ,कारतूस तथा एक बाइक बरामद किया है। इसी क्रम में लाइन बाजार थाना अंतर्गत थानाध्यक्ष सतीश सिंह अपनी टीम के साथ रात्रि ग्रस्त कररहे थे कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के नेवादा अंडरपास के पास से किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा होने वाले अपराधियों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराधी का इंतजार करने लगे तभी सामने से पैदल आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की बचाव में पुलिस द्वारा किए गए फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई मौके पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया नाम पूछने पर उसने अपना नाम नसीमअहमद उर्फ कल्लू कंगाली पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी थाना खेतासराय होना स्वीकार किया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल 32 बोर, कारतूस, 660 रुपए नगद बरामद किया है। इसका लंबा अपराधी इतिहास है यह खेतासराय थाने में पशु तस्करी में नामजद है। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकार शहर देवेश कुमार सिंह ने जिला स्थान पहुंचकर अपराधी से पूछताछ किया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।